Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 11

लोक प्रशासन एवं प्रबंधन, खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि

SIERRA INNOVATIONS

RAS

लोक प्रशासन एवं प्रबंधन, खेल एवं योग, व्यवहार एवं विधि

भाग – 11

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	प्रशासन एवं प्रबंधन	1
2.	संगठन के सिद्धांत	43
3.	शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उतरदायित्व, प्रत्यायोजन	54
4.	नव लोक प्रबंधन (NPM)	63
5.	प्रशासन के आधारभूत मूल्य	69
6.	प्रशासन पर नियंत्रण, विकास प्रशासन	74
7.	राजस्थान में प्रशासनिक ढाँचा एवं प्रशासनिक संस्कृति	87
8.	जिला प्रशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था	101
9.	संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग	113
10.	भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति	126
11.	भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्	131
12.	राष्ट्रीय एवं राज्य खेल पुरस्कार	137
13.	सकारात्मक जीवन पद्धति – योग	140
14.	भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व	147
15.	प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास	154
16.	भारतीय खिलाड़ियों की ओलम्पिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ एवं पैराओलम्पिक खेल में भागीदारी	156
17.	बुद्धि	160
18.	व्यक्तित्व	166
19.	अधिगम एवं अभिप्रेरणा	174
20.	प्रतिबल एवं प्रबंधन	182
21.	विधि की अवधारणा	187
22.	वर्तमान विधिक मुद्दे	199
23.	स्त्रियों एवं बालकों के विरूद्ध अपराध	212
24.	राजस्थान में महत्त्वपूर्ण भूमि विधियाँ	228
25.	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007	239

1 CHAPTER प्रशासन एवं प्रबंधन

प्रशासन

- प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के शब्द Ad-Ministiare से मिलकर बना है ।
- जिसमें Ministiare का अभिप्राय कार्यों को व्यवस्थित करना, देखभाल करना और सेवा प्रदान करने से है ।
- किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन कहा जाता है ।

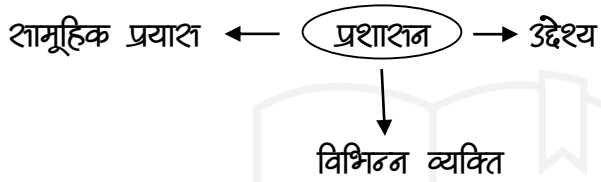

लूथर गुलिक के अनुसार :-
"प्रशासन का सम्बन्ध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है ।"

पर्सी मैकक्वीन के अनुसार – केन्द्रीय अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन ही लोक प्रशासन है ।
वुडरो विल्सन के अनुसार – लोक – प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है ।
एल.डी. व्हाईट के अनुसार – लोक – प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते है, जिनका उद्देश्य उपर्युक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है ।

प्रशासन की विशेषताएँ :-

1. प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है ।
2. प्रशासन के दो प्रकार है –
   I. लोक प्रशासन
   II. निजी प्रशासन
3. प्रशासन में कुछ निश्चित उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाता है ।
4. प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रायः बडे और विशाल संगठनों के लिए किया जाता है ।
5. प्रशासन के उद्देश्य व इसमें काम करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य में भिन्नता हो सकती है ।

डोनहम के अनुसार :-
"यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन की विफलता के कारण होगा ।"

प्रशासन के दृष्टिकोण :-

1. <u>प्रबन्धकीय दृष्टिकोण</u> :-
   - इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन में POSDCORB (Planning, Organising, Staffing, Directing, Co-ordination, Reporting, Budgeting) से सम्बन्धित गतिविधियाँ संपन्न करने वाले उच्च अधिकारी प्रशासन का भाग होते है ।

     अर्थात्

   - संगठन में केवल उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले व उनका क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति ही प्रशासन का भाग है ।

     नोट – वर्ष 1971 में इसमें E-Evaluation जोडा गया ।

2. <u>एकीकृत दृष्टिकोण</u> :-
   - इस दृष्टिकोण का मानना है कि संगठन में सभी कार्य व प्रक्रिया चाहे वे किसी भी स्तर के कर्मचारी द्वारा संपन्न की जाए, प्रशासन का भाग है ।

     अर्थात्

   - उच्च पदाधिकारी, तकनीकी कर्मचारी, लिपिकीय वर्ग व सहायक कर्मचारी भी प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है ।
   - एकीकृत दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण माना जाता है ।

लोक–प्रशासन

- लोक प्रशासन, प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत रहकर राजनीतिक निर्णयों को कार्यरूप में लागू करता है ।
- <u>एपलबी के अनुसार</u> – "नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है ।"
- <u>अल्बर्ट साइमन के अनुसार</u> – "साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है ।"
- <u>फिफनर के अनुसार</u> – "सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्स–रे मशीन का संचालन हो या टकसाल में सिक्के डालना हो ।"

<u>प्रशासन</u>	<u>लोक–प्रशासन</u>
1. प्रशासन व्यापक दृष्टिकोण है ।	1. यह संकुचित दृष्टिकोण है क्योंकि यह प्रशासन का भाग है । तथा सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है ।
2. प्रशासन एक क्रिया–प्रक्रिया दोनों है ।	2. लोक प्रशासन एक तंत्र है जिसके द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य संपन्न किए जाते है ।
3. इसका सम्बन्ध विभिन्न लोगों से कार्य करवाने से है ।	3. यह दोहरे स्वरूप वाला है – विषय तंत्र
4. किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है ।	4. लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है ।

शासन	लोक – प्रशासन
1. शासन का सम्बन्ध सरकार से होता है ।	1. लोक प्रशासन का सम्बन्ध नौकरशाही से होता है ।
2. इसका संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है ।	2. इसका संचालन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।
3. यह निर्देश संविधान से प्राप्त करता है ।	3. लोक प्रशासन सरकार के निर्देशन पर कार्य करता है ।
4. यह जनता के प्रति उत्तरदायी है अतः इन्हें जनसेवक कहा जाता है ।	4. ये सरकार के प्रति उत्तरदायी है अतः इन्हें सरकारी सेवक कहा जाता है ।
5. शासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण है ।	5. लोक प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन करता है ।

प्रबन्ध

- प्रशासन या संगठन का वह भाग जो संसाधनों के समुचित उपयोग, उनमें समन्वय तथा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में उनका संचालन करना सुनिश्चित करवाता है ।
- प्रबन्ध द्वारा प्रायः लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित POSDCORB से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न किए जाते है ।

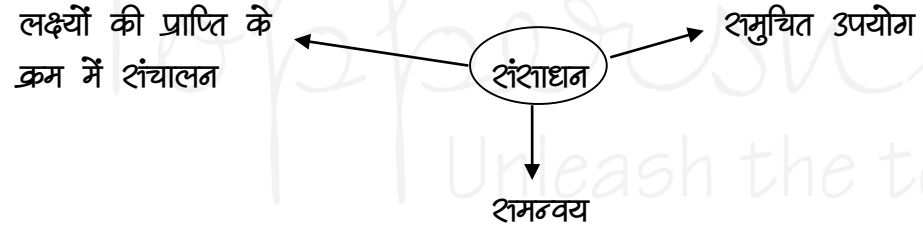

Toppersnotes
Unleash the topper in you

<u>प्रशासन व प्रबन्ध में अन्तर</u> :- इनके मध्य सर्वप्रथम अन्तर ऑलिवर शेल्डर द्वारा सन् 1923 में 'फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेन्ट' पुस्तक में किया गया ।

प्रशासन	प्रबन्ध
1. प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है ।	1. प्रबन्ध प्रशासन का ही अंग है अतः यह संकुचित अवधारणा है ।
2. प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन के लक्ष्यों को निर्धारित करना है ।	2. प्रबन्ध इन निर्धारित लक्ष्यों (उक्त) को प्राप्त करने का प्रयास करता है ।
3. प्रशासन संगठन में प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है ।	3. प्रबन्ध संगठन में प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है ।

प्रशासन व प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न विचारधाराएँ

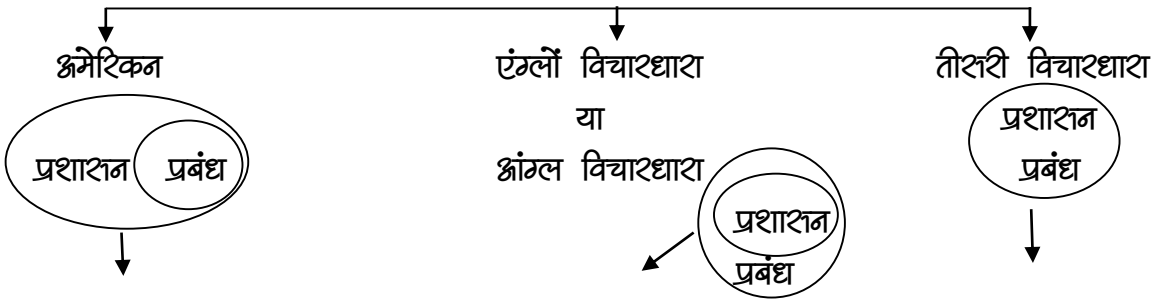

- यह सर्वमान्य विचारधारा है जिसका मानना है कि प्रशासन व्यापक है तथा प्रबन्ध इसमें सम्मिलित है ।
- शुल्ज, रॉबिन्सन ने इसका समर्थन किया

- इस विचारधारा का मानना है कि प्रबन्ध एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रशासन सम्मिलित है ।
- डे.पी. डेनियल, डेम्स लुण्डी

- इस विचारधारा का मानना है कि प्रबंध व प्रशासन एक-दूसरे के पर्यायवाची है तथा इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का अंतर नही है ।
- फॉलेट, उर्विक, M.P. शर्मा

लोक प्रशासन की प्रकृति

1. <u>प्रबन्धकीय व एकीकृत</u> :-

<u>प्रबन्धकीय</u> :-

- इस दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासकीय निर्णय लेने, नीतियों व कानूनों के व्यावहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने से है ।

  अर्थात्

  संगठन में उत्तरदायी व उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति तथा उनके कार्य लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट करते है ।
- इसके समर्थक :- साइमन, स्मिथबर्न है ।

<u>एकीकृत :-</u>

- संगठन में उच्च स्तर से लेकर निम्नतम स्तर तक कार्यरत समस्त कार्मिकों की क्रियाओं को यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन की प्रकृति में सम्मिलित करता है ।
- समर्थक : विलोबी, व्हाईट है ।

2. <u>लोक प्रशासन विज्ञान या कला के रूप में</u> :- समर्थक - विलोबी, विल्सन, मर्सन

<u>लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में</u> :-

(a). लोक प्रशासन में विज्ञान की भाँति सर्वमान्य सिद्धान्त व नियम है । ये सिद्धान्त सार्वभौमिक है । उदाहरण- पदसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा (motivation), केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण आदि ।

(b). लोक प्रशासन में विज्ञान की भाँति विभिन्न वैज्ञानिक विधियाँ प्रयुक्त की जाती है ।
उदाहरण – CPM (Critical Path Method) , PERT इत्यादि ।

(c). लोक प्रशासन विज्ञान की भाँति मूल्य मुक्त है ।

(d). लोक प्रशासन में इसके सिद्धान्तों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है ।

(e). लोक प्रशासन के विशेषज्ञ आज चिकित्सक, इंजीनियर व मनोवैज्ञानिक की भाँति परामर्शदाता की भूमिका निभाने लगे है ।

(f). लोक प्रशासन के प्रमुख ग्रन्थ अर्थशास्त्र, रिपब्लिक, आईन-ए-अकबरी इस विषय को प्रामाणिक व वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में सहायक है ।

लोक प्रशासन कला के रूप में :-

समर्थक – महादेव प्रसाद शर्मा (भारत में लोक प्रशासन के पिता), टीड

(a). प्रशासक बनने के लिए विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिभा का धनी व्यक्ति ही अच्छा कलाकार हो सकता है ।

(b). प्रशासन कला की भाँति व्यक्तित्व पर निर्भर करता है ।

(c). प्रत्येक कलाकार में सृजनात्मक क्षमता होती है ठीक उसी प्रकार एक प्रशासक भी सृजनात्मक क्षमता के माध्यम से नवाचार करता है ।

(d). प्रशासन कला की भाँति देशकाल के अनुसार परिवर्तित होता है ।

(e). प्रत्येक कला की अभिव्यक्ति हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार एक प्रशासक का माध्यम संगठन, संगठन की नीतियाँ एवं संगठन का परिवेश है ।

(f). कलाकार बनने हेतु प्रशिक्षण व अभ्यास की आवश्यकता होती है इसी प्रकार प्रशासन में प्रशासनिक क्षमता / कौशल/दक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ।

(g). जिस प्रकार कला का विकास धीरे-धीरे हुआ है उसी प्रकार प्रशासन का विकास भी निरन्तर हो रहा है ।

निष्कर्ष :- कहा जा सकता है कि – लोक प्रशासन न तो कला है न विज्ञान है बल्कि यह सामाजिक विज्ञान का विकसित होता विषय है ।

लोक प्रशासन का क्षेत्र :-

1. संकुचित दृष्टिकोण :-

- इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रशासन का सम्बन्ध केवल कार्यपालिका से है जो विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों के क्रियान्वयन करने वाला तन्त्र है ।
- इस दृष्टिकोण के अनुसार विधायिका व न्यायपालिका लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित नही होते है ।
- समर्थक = वाइमन, स्मिथबर्न

2. <u>व्यापक दृष्टिकोण</u> :-

- इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि लोक प्रशासन का सम्बन्ध शासन के तीनों अंगो व्यवस्थापिका कार्यपालिका व न्यायपालिका से है ।
- लोक प्रशासन व्यवस्थापिका को विभिन्न आँकडे उपलब्ध करवाने के साथ सदन संचालन में सहायता करता है ।
- कार्यपालिका को लोक प्रशासन नीति - निर्माण और नीति-क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है।
- प्रशासन न्यायपालिका के विभिन्न आदेशों की क्रियान्विति, विभिन्न गवाह और साक्ष्य लाना आदि लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आते है ।

3. <u>POSDCORB दृष्टिकोण</u> :-

- इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया जिसके अनुसार -

P - Planning	= संसाधनों का सदुपयोग विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा का निर्धारण करना ।
O - Organising	= Man Method Material Machine को संगठित करना ।
S - Staffing	= कार्मिकों की भर्ती, वेतन प्रशिक्षण, पदोन्नति सम्बन्धी कार्य करना ।
D - Directing	= उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान करना ।
Co - Co-ordination	= संगठन में विभिन्न व्यक्तियों व संगठन की विभिन्न इकाईयों के मध्य समन्वय स्थापित करना ।
R - Reporting	= प्रत्येक अधीनस्थ अपने कार्यो की प्रगति, बाधाओं से उच्च अधिकारी को अवगत कराए ।
B - Budgeting	= संगठन की आय-व्यय का ब्यौरा, वित्त प्रशासन में O_2 का कार्य
E - Evaluation	= यह शब्द वर्ष 1971 में जोडा गया था ।

<u>आलोचना</u> :-

1. प्रशासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण, मूल्यांकन, जनसम्पर्क करना है जो कि पूरे POSDCORB सिद्धान्त से गायब है ।
2. जनकल्याण जो लोक प्रशासन का दर्शन है, POSDCORB सिद्धान्त में कही भी दिखाई नहीं देता है ।
3. POSDCORB मानव सम्बन्ध उपागम का विरोधी है जिसमें मानवीय सम्बन्धों को स्थान नहीं दिया है ।
4. यह सिद्धान्त लोक प्रशासन की केवल प्रबन्धकीय नीति की व्याख्या करता है ।

4. <u>पाठ्य विषयवस्तु दृष्टिकोण</u> :-

- लेविस मेरियम समर्थित इस दृष्टिकोण का मानना है कि POSDCORB से लोक प्रशासन नहीं चलता है बल्कि यह सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं जैसे- चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, समाज कल्याण जैसी विषय सामग्री पर निर्भर है ।
- मेरियम का मानना है कि :- "यह कैंची के दो फलकों के रूप में है जिसमें एक फलक POSDCORB से युक्त ज्ञान है तो दूसरा फलक विषय का ज्ञान है, अतः दोनों फलक धारदार होने चाहिए ।"

5. <u>लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण</u> :-

- इस दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन लोक नीति क्रियान्वयन के साथ-साथ लोक नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
- समर्थक - ड्रोर, लासवेल

6. <u>लोक निजी प्रशासन दृष्टिकोण</u> :-

इसमें 2 विचारधाराएँ है

लोक - निजी में अन्तर नहीं है ।	लोक -निजी में अन्तर है ।
समर्थक - फॉलेट	समर्थक - साइमन
- गुलिक	- एपलबी
- उर्विक	

7. <u>आधुनिक दृष्टिकोण</u> :-

- इसके अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है ।

अर्थात्

- जिस प्रकार राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होती है उसी प्रकार लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र भी बढता जाता है ।

<u>विभिन्न मान्यताएँ</u> :-

1. राजनीति-प्रशासन द्विभाजन सिद्धान्त को अस्वीकृत करता है ।
2. लोक व निजी प्रशासन समान है ।
3. आधुनिक दृष्टिकोण प्रशासन में 3 E [Economy (मितव्ययिता), Effectiveness (प्रभावशीलता), Efficiency (कार्यकुशलता)] अवधारणा पर बल देता है ।

<u>लोक प्रशासन का महत्व</u> :-

1. <u>सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने का साधन</u> :- राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन ही एकमात्र माध्यम रहा है क्योंकि यह सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों हेतु बनाई गई नीतियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है ।

2. <u>जनकल्याण का माध्यम</u> :-

- भारत में लोक प्रशासन संविधान के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से समाज के दीन-हीन व निर्योग्यता युक्त व्यक्तियों हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रयासों के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाता है ।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, आवास आदि समस्त मूलभूत मानवीय सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से होता है, अतः कहा जाता है - "प्रशासन जन्म से लेकर कब तक विद्यमान है" - वाल्डो (बुक :- एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट-1948)

3. <u>एकता, अखण्डता व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना</u> :-

यद्यपि सीमा पर रक्षा का कार्य सैनिक प्रशासन का है किन्तु शान्ति काल में सीमाओं की रक्षा, राष्ट्र की आन्तरिक अखण्डता, शान्ति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द व समरसता बनाए रखने का दायित्व लोक प्रशासन का ही है ।

4. <u>लोकतंत्र का वाहक व रक्षक</u> :- आम व्यक्तियों तक शासकीय कार्यों की पहुँच सुनिश्चित करना, निष्पक्ष चुनाव करना, जन-शिकायतों का निवारण, राजनैतिक चेतना में वृद्धि करना, विभिन्न विकास कार्यों में जनसहभागिता सुनिश्चित करना लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है ।

5. <u>सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में</u> -

I. <u>सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में</u> :- विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज आदि कुरीतियों का समाधान प्रशासन द्वारा निर्मित सामाजिक नीतियों, सामाजिक नियमों के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया जाता है ।

II. <u>आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में</u> :- देश में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, समाजवाद-पूँजीवाद में सामंजस्य, आर्थिक संसाधनों का सही दिशा में प्रयोग करना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य किए जाते है ।

6. <u>सभ्यता, संस्कृति व कला के संरक्षणकर्ता के रूप में</u> :- लोक प्रशासन द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता व विरासत का संरक्षण, चित्रकला, वास्तुकला व संगीतकला का संरक्षण व विकास व देश के गौरवशाली मूल्यों का संरक्षण किया जाता है ।

7. <u>विधि व न्याय प्रदान करना</u> :- लोक प्रशासन का कर्त्तव्य है कि -

I. संविधान द्वारा निर्मित कानून, नियम, नीतियों व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राजकीय कार्यों का संचालन करना ।

II. विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दण्डित करवाना ।

III. न्यायपालिका के निर्णयों की पालना सुनिश्चित करना ।

8. आजीविका का माध्यम :-

- अधिकतर देशों में कार्यशील जनसंख्या का एक बडा हिस्सा राजकीय सेवाओं में कार्य करता है ।
- एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड, USA में 18%, फ्रांस में 33% व स्वीडन में 38% लोग राजकीय सेवाओं में कार्यरत है ।

9. लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में :-

- लोक प्रशासन के अध्ययन से शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ प्रशासन की एक समझ विकसित होती है ।
- दूसरी ओर इसका अध्ययन करने वालों में अच्छे नागरिक बनने के गुणों का विकास होता है ।
  विल्सन के अनुसार - ''लोक प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है ।''
  डोनहम के अनुसार - ''वर्तमान सभ्यता की असफलता, प्रशासन की असफलता है ।''
  एपलबी के अनुसार - ''प्रशासन के बिना सरकार मात्र परिचर्चा क्लब है ।''

लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि के कारण (कार्यक्षेत्र में) :-

1. ''पुलिस राज्य'' के स्थान पर 'लोक कल्याणकारी' राज्य की अवधारणा का उद्भव
2. जनसंख्या वृद्धि
3. पर्यावरणीय निम्नीकरण (अकाल, सूखा, बाढ, ग्लोबल वार्मिंग आदि)
4. वर्ग संघर्ष
5. साम्प्रदायिक दंगे, जातीय हिंसा आदि
6. नस्ल भेद
7. साइबर क्राइम
8. औद्योगिक क्रान्ति
9. आतंकवाद
10. नक्सलवाद

LPG (1990) के बाद लोक प्रशासन का बदलता स्वरूप

1. राज्य का ''पश्च बेलन सिद्धान्त'' तथा ''गैर-नौकरशाहीकरण'' (Golden Handshake Scheme) पर बल दिया ।
2. लोक प्रशासन नियंत्रणकर्ता के स्थान पर प्रोत्साहनकर्ता बन गया है ।
3. प्रशासन में 3E का समावेश हुआ ।
4. लोक प्रशासन में जनसम्पर्क और जनसहभागिता पर बल दिया गया ।
5. नागरिक अधिकार पत्र, RTI, सामाजिक अंकेक्षण (Social Auditing), उपभोक्ता संरक्षण जैसे नवाचार ।
6. प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का बढता प्रयोग (E-governance) ।
7. प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण में World Bank, IMF, UNO आदि की भूमिका में वृद्धि ।

विकासशील व विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका

विकसित देशों के प्रशासन की विशेषताएँ :-

1. विकेन्द्रीकृत प्रशासन
2. राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता
3. पारदर्शिता युक्त, जवाबदेही व उत्तरदायी प्रशासन (TAR)
4. पेशेवर नौकरशाही
5. जनसहभागिता युक्त प्रशासन
6. प्रशासनिक संरचना तार्किक व स्वतंत्र

विकासशील देशों के प्रशासन की विशेषताएँ :-

1. प्रशासन में भ्रष्टाचार व लालफीताशाही
2. प्रशासन औपनिवेशिक विरासत
3. जनसहभागिता की कमी
4. प्रशासन में प्रतिबद्धता का अभाव
5. संक्रमणकालीन प्रशासनिक व्यवस्था
6. अकर्मण्यता व रूढिवादिता

प्रशासन की भूमिका :-

1. सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने का साधन
2. जनकल्याण का माध्यम
3. एकता, अखण्डता व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना
4. लोकतंत्र का वाहक व रक्षक
5. सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में
6. सभ्यता, संस्कृति व कला के संरक्षणकर्ता के रूप में
7. विधि व न्याय प्रदान करना
8. आजीविका का माध्यम
9. लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में ।
10. प्राकृतिक व मानवीय आपदा के निवारक के रूप में ।
11. मानवाधिकारों का संरक्षणकर्ता ।
12. प्रशासनिक नीतियों का प्रसारणकर्ता व प्रशासनिक नवाचारों का प्रारम्भकर्ता के रूप में ।
13. राजनैतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनकर्ता के रूप में ।

Toppersnotes Unleash the topper in you

विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका :-

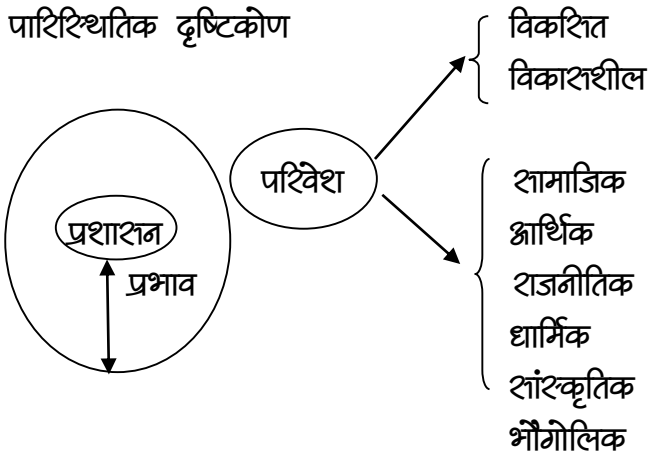

1. विकासशील देश – गरीबी, भूखमरी, जैसी समस्याएँ थी । विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान हेतु विकास प्रशासन
   विकसित देश – वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप नवीन लोकप्रशासन ।
2. लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन है । किन्तु लोक प्रशासन की भूमिका में विकसित देशों में गुणात्मक ज्यादा है तथा विकासशील देशों में मात्रात्मक ज्यादा है ।
3. लोक प्रशासन राजनीति परिवर्तन और विकास का साधन है लोक प्रशासन की यह भूमिका विकसित और विकासशील देशों में अलग-अलग होती है । लोक प्रशासन की यह भूमिका विकासशील देशों में अधिक महत्वपूर्ण होती है बजाए विकसित देशों के ।
   <u>असंतुलित राजनीति</u> – यह विकासशील देशों की विशेषता होती है । इसका अर्थ है विकासशील देशों का जितना प्रशासन परिपक्व है राजनीति उतनी परिपक्व नहीं है क्योंकि प्रशासन का विकास औपनिवेशिक काल में हुआ जबकि राजनीति का विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ ।
4. नीति निर्माण में प्रशासन की भूमिका – विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में प्रशासन की भूमिका नीति निर्माण में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ।
5. "एफ डब्ल्यू रिग्स" :- विकसित विकासशील देशों की तुलना की तो विकासशील देशों की कुछ विशेषताएँ पायी जाती है –
   A- विकासशील देशों की एक महत्वपूर्ण विशेषता विषम जातीयता होती है । एक ही समय में अलग-अलग प्रभावों, परम्पराओं, रीति रिवाजों का अस्तित्व होना ।
   रिग्स ने सन् 1959 में अपनी थ्योरी दी "त्रिऊमीय समाज और साला प्रतिमान" के नाम से सिद्धान्त दिया । (साला स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ सरकारी कर्मचारी होता है ।)
   B- <u>औपचारिकता</u> :- सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी

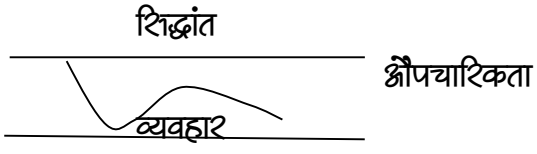

लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में विकास

लोक प्रशासन का उद्भव अमेरिका में क्यों ?

1. USA में "लूट प्रणाली (Spoil system)" की समाप्ति होना ।
2. अमेरिका में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव होना ।
3. तीव्र औद्योगीकरण व बडे पैमाने पर सामाजिक विस्थापन होना ।
4. अमेरिकी संगठनों में प्रबन्धकीय जटिलताएँ होना ।

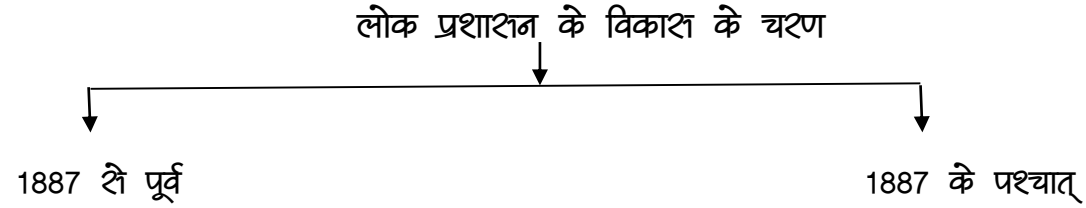

प्राचीन राजनैतिक चिन्तकों द्वारा प्रशासन का अध्ययन

कौटिल्य – अर्थशास्त्र प्लेटो – रिपब्लिक अरस्तु – पॉलिटिक्स मैकियावली – द प्रिन्स ↓ कैमरलवाद (जर्मनी व ऑस्ट्रिया) द्वारा प्रशासन के सामान्य सिद्धान्तों का प्रचार, प्रसार किया । (जॉर्ज जिन्के) ↓ लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन 'प्रशा' में प्रारंभ हुआ । ↓ 18वीं शताब्दी में अमेरिका के वित्त मंत्री हेमिल्टन द्वारा 'द फेडरलिस्ट' नामक लेख में लोक प्रशासन शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की गई । ↓ वर्ष 1812 में चार्ल्स ज्या बुनिन द्वारा 'प्रिंसिंपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक' (फ्रेंच भाषा) नामक रचना को लोक प्रशासन की प्रथम रचना माना जाता है ।	1. राजनीतिक – प्रशासन द्विविभाजन (1887–1926) 2. सिद्धान्तों का स्वर्णकाल (1927–1937) 3. चुनौतियों का काल (1938–1947) 4. पहचान का संकट (1948–1970) 5. अन्तः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल या नवलोक प्रशासन का काल (1971–1990) 6. LPG व लोक प्रशासन या नवलोक प्रबंधन का काल (1991.....)

प्रथम चरण (राजनीति–प्रशासन द्विविभाजन) (1887–1926 ई.) :–

- 1887 ई. में ''द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन'' नामक लेख में वुडरो विल्सन द्वारा राजनीति प्रशासन द्विविभाजन विचारधारा का प्रतिपादन किया गया । अतः वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है ।
- वुडरो विल्सन का मानना था कि संविधान की रचना करना बहुत सरल है किन्तु इसे चलाना बहुत कठिन है ।
- इसी क्रम में वर्ष 1900 में अमेरिका के गुडनाऊ ने ''Politics and Administration'' पुस्तक में इस द्विविभाजन का समर्थन किया ।
- गुडनाऊ को अमेरिका में लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है ।
- गुडनाऊ का मानना था कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन इसका क्रियान्वयन करता है ।
- वर्ष 1920 में मैक्स वैबर ने नौकरशाही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ।
- वर्ष 1926 में लोक प्रशासन पर प्रथम पाठ्यपुस्तक "Introduction to the study of Public Administration" की रचना L.D. व्हाईट के द्वारा की गई । इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्यपुस्तक कहा जाता है ।

द्वितीय चरण (सिद्धान्तों का स्वर्णकाल) (1927–37 ई.) :–

- इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धान्तों का विकास हुआ जो निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों में लिखे गए–
  1. विलोबी की पुस्तक – "The Principle of Public Administration" (1927)
  2. मूने व रैले की पुस्तक – "Onward industry" (1930)
  3. गुलिक व उर्विक की पुस्तक – "Papers on Science of Administration" (1937)
  4. फेयॉल की पुस्तक – "Industrial and General Management"
- लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर खारिज किया ।
- उल्लेखनीय है कि फेयॉल ने 14, मुने–रैले ने 4, गुलिक ने 10 तथा उर्विक ने 29 व 8 सिद्धान्त दिए ।
- फेयोल व गुलिक ने तीसरा सिद्धांत आदर्श संगठन सिद्धांत/शास्त्रीय विचारधारा दिया ।
- इस चरण में कुल 36 सिद्धान्त दिए गए ।
- इस चरण के चिंतकों को शास्त्रीय चिंतक कहा जाता है ।

तृतीय चरण (चुनौतियों का काल) (1938–47 ई.) :–

- इस चरण में प्रशासन से सम्बन्धित सिद्धान्तों को लोकप्रियता के बावजूद गम्भीर चुनौतियों व आलोचनाओं का शिकार होना पडा ।
- 1939 ई. आल्टन मेयो ने मानव संबंध सिद्धान्त दिया ।

- 1938 ई. में चेस्टर बर्नार्ड द्वारा "The Function of Executive" पुस्तक में किसी भी प्रशासनिक सिद्धान्त का उल्लेख नहीं किया । अतः लोक प्रशासन के विद्वानों को इससे निराशा हुई ।
- 1946 ई. में हर्बर्ट साइमन ने "Administrative Behaviour" नामक पुस्तक में प्रशासनिक सिद्धान्तों को मुहावरे व लोकोक्तियों में कहा ।
- इसी क्रम में वर्ष 1947 में रॉबर्ट डहल ने "Science of Public Administration: Three Problems" पुस्तक में लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में तीन बाधाओं का उल्लेख किया जो क्रमशः प्रशासन का मूल्य युक्त अध्ययन, मानव व्यवहार की परिवर्तनीयता, सामाजिक परिवेश थी ।

चतुर्थ चरण (पहचान का संकट) (1948–1970 ई.) :-

- इस चरण में लोक प्रशासन के कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान की ओर चले गए तथा जॉन गॉस ने वर्ष 1950 में ''Trends in the theory of Public Administration'' नामक लेख में लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा बताया लेकिन लोक प्रशासन विषय के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ नई अवधारणाओं का विकास हुआ । मार्टिन ने इसका समर्थन किया ।

उदा. – तुलनात्मक लोक प्रशासन (1952)
विकास प्रशासन (1955)
New Public Administration (1968)
जन चयन विचारधारा (1970)

पाँचवां चरण (अन्तः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल या नव – लोक प्रशासन काल) (1971–90 ई.) :-

- इस चरण में लोक प्रशासन ने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबन्धन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के साथ गहरे (घनिष्ठ) सम्बन्ध स्थापित किए ।
- इस चरण में पारम्परिक लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धान्तों राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, संगठन में पदसोपानी व्यवस्था, प्रशासन का मूल्य–मुक्त अध्ययन आदि को खारिज/नकार दिया ।

प्रशासन की नीति निर्माण में भूमिका :-

खारिज क्यों (राजनीति)	पक्ष में तर्क (प्रशासन)
समय नहीं होना ।	योग्य है ।
कार्य भार ज्यादा होना ।	अनुभवी और प्रशिक्षित है ।
तकनीकी योग्यता नहीं होना ।	तकनीकी योग्यता है ।
अनुभव नहीं है प्रशिक्षण नहीं है ।	आँकडों की उपलब्धता है ।
स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी नहीं है ।	स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी ।

प्रशासन की नीति निर्माण में भूमिका आवश्यक हो जाती है । जब प्रशासन नीति निर्माण में भूमिका निभाता है तभी नीति निर्माण में वास्तविकता आती है । नीतियों के क्रियान्वयन के प्रति वचनबद्धता आती है । विकास प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई । इन संकल्पनाओं ने साध्यों पर जोर दिया साधनों पर नही ।

- 1980 के दशक में LPG की नीतियों की शुरूआत हो गई थी ।
  लोक प्रशासन की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लग गया था ।
- 1988 ई. में अमेरिका में "द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन" का आयोजन किया गया ।
  → नवीन लोक प्रबंधन की संकल्पना आयी ।
  (New Public Management)

<u>छठा चरण (1991 से आज तक)</u> :- वर्तमान प्रवृत्तियाँ/लोकप्रशासन और LPG

1. लोकप्रशासन के अर्थ में परिवर्तन – वर्तमान समय में सरकारी के साथ गैर-सरकारी/स्वयंसेवी समस्याओं को लोक प्रशासन में शामिल कर लिया ।
2. निजी कंपनियों के कार्यों को शामिल किया जो सरकार या जनता के पैसे पर निर्भर है ।
3. वर्तमान समय में सरकारी नहीं सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन हो गया ।
4. जब लोक प्रशासन की प्रासंगिता पर (निजीकरण के बाद) प्रश्न चिन्ह लगा तो हमने देखा लोक-प्रशासन की प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आयी ।
5. लोक प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन अवश्य हुआ ।
   निजीकरण – बाजार की भूमिका
   ↓
   बाजार की कमियाँ
   1. माँग एवं पूर्ति के सिद्धान्त पर चलता है ।
      Demand and Supply = Need and Supply
   2. प्रतिस्पर्धा
6. PPP – लोक निजी भागीदारी
7. वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने सुशासन या Good Governance की संकल्पना दी ।
8. नवीन लोक प्रबंधन की संकल्पना आयी इसमें 3E's संकल्पना पर बल दिया गया ।
   3E's
   - Efficiency - कार्यकुशलता/दक्षता
   - Economy - मितव्ययता
   - Effectiveness - प्रभावशीलता
9. नियामकीय प्राधिकरणों का उदय हुआ ।
10. कॉर्पोरेट गवर्नेंस + CSR की संकल्पनाओं का उदय हुआ ।
    - वर्ष 2008 में "तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन" का आयोजन हुआ ।
      ↓
      लोक प्रशासन के नये अर्थ को इस सम्मेलन में मान्यता मिली थी ।

निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन के विकास के चरण

1. राजनीति-प्रशासन द्विविभाजन (1900-26)
2. प्रशासन के सिद्धान्त (1927-37)
3. सिद्धान्तों को चुनौती व प्रतिक्रिया (1938-50)
4. लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की भाँति (1950-70)
5. लोक प्रशासन प्रबन्ध की भाँति (1950-56)
6. लोक प्रशासन, लोक प्रशासन की तरह (1971....)

भारत में लोक प्रशासन विषय का विकास :-

- 1937 ई. में मद्रास यूनिवर्सिटी सर्वप्रथम लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्रोग्राम प्रारम्भ हुआ (प्रो. बेनी प्रसाद के प्रयासों से) ।
- 1938 ई. में ऐसा ही डिप्लोमा प्रोग्राम - इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ ।
- 1945 ई. में ऐसा ही डिप्लोमा प्रोग्राम - लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ ।
- 1949 ई. में लोक प्रशासन का प्रथम विभाग - नागपुर विश्वविद्यालय, जिसके प्रथम विभागाध्यक्ष - महादेव प्रसाद शर्मा (भारत में लोक प्रशासन का पिता) ।
- 1954 ई. में दिल्ली में एपलबी समिति की सिफारिश पर IIPA (Indian Institute of Public Administration) की स्थापना हुई ।
- 1959 ई. में लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लोक प्रशासन विभाग की स्थापना हुई ।
- 1975 ई. में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रो. M.B. माथुर के प्रयासों से लोक प्रशासन विभाग की स्थापना हुई । अतः राज. में लोक प्रशासन का पिता - M.B. माथुर ।
- 1987 ई. में UPSC द्वारा लोक प्रशासन को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किया गया ।

भारत में लोक प्रशासन के चार मठ :-

- हैदराबाद
- चण्डीगढ
- जयपुर
- लखनऊ
  - वर्तमान में लगभग भारत में सभी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन हेतु अलग विभाग स्थापित हैं ।

नवीन लोक प्रशासन (NPA) :-

- 1960 के दशक में विकसित देश (विशेषकर अमेरिका की परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में) परम्परागत लोक प्रशासन में नवीन विचारों का समावेश और नवीन विचारों के समावेश के बाद जो नयी संकल्पना आयी उसे ही नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दे दी गई ।
- यह संकल्पना भी पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर आधारित संकल्पना थी ।
  परम्परागत लोक प्रशासन + नवीन विचार = नवीन लोकप्रशासन

- संयुक्त राज्य अमेरिका में पनपी यह विचारधारा जिसने लोक प्रशासन को जन समस्याओं के समाधान के क्रम में ठोस व व्यावहारिक भूमिका निभाने की वकालात की ।

NPA के उदय के कारण :-

1. अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष व तनाव होने के कारण ।
2. <u>हनी रिपोर्ट (1967)</u>

   विषय - सार्वजनिक सेवाओं से सम्बन्धी उच्च शिक्षा

   सिफारिशें -

   I. MA में छात्रवृत्तियों की घोषणा
   II. लोक प्रशासन में शोधकार्य करने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता
   III. लोक सेवा सम्बन्धी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

3. <u>फिलोडेल्फिया सम्मेलन (1967)</u>

   अध्यक्ष - चार्ल्स वर्थ

   विषय - लोक प्रशासन के सिद्धान्त व व्यवहार

   मुख्य बातें -

   I. पदसोपानी व्यवस्था को लचीला बनाने पर बल देना ।
   II. समाज में सामाजिक समता की स्थापना करना ।
   III. लोक प्रशासन का ध्यान निर्धनता, बेरोजगारी, प्रदूषण आदि सामाजिक समस्याओं पर होना चाहिए ।
   IV. यह सम्मेलन राजनीति-प्रशासन द्विविभाजन विचारधारा का विरोध करता है ।

4. <u>मिन्नोब्रुक सम्मेलन (1968)</u> :-

   अध्यक्ष :- वाल्डो

   - इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण मुद्दा लोक प्रशासन में मूल्य निरपेक्षता व इसकी प्रासंगिकता था ।
   - वाल्डो ने "Public Administration in a Time of Turbulance" नामक लेख को प्रकाशित किया ।
   - इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के लक्ष्य के रूप में प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता तथा परिवर्तन को चिन्हित किया गया ।

नव लोक प्रशासन के लक्ष्य :-

1. <u>प्रासंगिकता</u> :- लोक प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रासंगिकता सहित व्यावहारिकता पर बल दिया गया ।
2. <u>मूल्य</u> :- लोक प्रशासन में मूल्य मुक्तता के स्थान पर मूल्य उन्मुक्तता पर बल दिया गया क्योंकि मूल्य युक्त प्रशासन का शोषित, दमित, सुविधाविहीन वर्ग की ओर झुकाव रहता है ।

3. <u>सामाजिक समता</u> :– नव लोक प्रशासन समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला प्रशासन है इसीलिए NPA को 'जनोन्मुखी प्रशासन' भी कहा जाता है ।
4. <u>परिवर्तन</u> :– NPA सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का समर्थक है ।

<u>NPA की विशेषताएँ</u> :–

1. NPA राजनीति–प्रशासन द्विविभाजन सिद्धान्त का प्रबल विरोध करता है ।
2. NPA मानवीय दृष्टिकोण का समर्थक है ।
3. NPA के लक्ष्य प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता व परिवर्तन है ।
4. यह कठोर पदसोपानिक व्यवस्था का विरोध करता है ।
5. NPA के लक्ष्यों को प्राप्ति का साधन 4 D है –
   Decentralisation (विकेन्द्रीकरण)
   Delegation (प्रत्यायोजन)
   Democratisation (लोकतंत्रीकरण)
   Debureaucratisation (डिब्यूरोक्रेआइजेशन)
6. यह ग्राहकोन्मुखता पर बल देता है ।
7. <u>आलोचनाएँ</u> –
   A. चूँकि यह विचारधारा अमेरिका में विकसित हुई अतः विकासशील देशों के लिए यह अधिक प्रासंगिक नहीं है ।
   B. एक तरफ NPA प्रशासनिक तंत्र पर अपनी निर्भरता दर्शाता है, दूसरी तरफ यह अवधारणा विनौकरशाही का समर्थन करती है जो एक–दूसरे के विरोधी है ।
   C. NPA मूल्यों पर अत्यधिक बल देता है ।
   D. यह संकल्पना एक संवैधानिक संकल्पना बनकर रह गयी तथा व्यावहारिक रूप नही अपना सकी । इसके पीछे 2 कारण थे –
      1. राजनीति का सहयोग नही मिला ।
      2. साध्य पर जोर दिया साधनों पर नहीं ।

मिन्नोब्रुक सम्मेलन प्रथम (1968)	मिन्नोब्रुक सम्मेलन द्वितीय (1988)	मिन्नोब्रुक सम्मेलन तृतीय (2008)
1. इसमें अधिकतर सहभागी युवा थे ।	1. इसमें युवा व वरिष्ठ सहयोगी थे ।	1. 13 देशों के 220 प्रतिभागी थे ।
2. इसका आयोजन अमेरिकी सामाजिक आर्थिक उथल–पुथल के दौरान हुआ ।	2. इसका आयोजन विश्वव्यापी आर्थिक सुधारों (LPG) के दौरान हुआ ।	2. इसमें चर्चा के मुख्य बिन्दु प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता, साझा प्रयास आदि थे ।